

Statement showing Press Clippings regarding coverage of Report of the Comptroller and Auditor General of India on Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana (DDUGJY) and Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana (SAUBHAGYA), Government of Uttar Pradesh, Report No. 7 of the year 2025 (Performance Audit – Commercial) in Newspapers

Date of laying/tabling of Audit Report in the State Legislature: 24.12.2025

Name of the Newspaper	दैनिक जागरण
Date	25.12.2025
Edition (H/E)	हिंदी
Page No.	11

मकसद में पूरी तरह कामयाब नहीं हुई गांव की बिजली योजनाएं

राज्य ब्यूरो, जागरण • लखनऊ: गांव की बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ ही हर घर बिजली पहुंचाने के मकसद से केंद्र सरकार ने जिस दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) को शुरू किया था उसके क्रियान्वयन से लेकर वित्तीय प्रबंधन में तमाम खामियां मिली हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में इस पर सवाल उठाते हुए कहा गया है कि 29 से 49 माह देर तक जहां काम हुए वहीं तय लक्ष्य के मुताबिक एटीएंडसी (तकनीकी एवं वाणिज्यिक) हानियों में भी कमी नहीं आई।

बुधवार को सीएजी की डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य पर विधानमंडल में रिपोर्ट पेश की गई।

- उप में सौभाग्य और ग्राम ज्योति योजना के क्रियान्वयन पर सीएजी ने उठाए सवाल
- विधानमंडल में पेश की गई रिपोर्ट, वित्तीय प्रबंधन में भी खामियां मिली सीएजी को



रिपोर्ट में बताया गया है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से दिसंबर 2014 में प्रारंभ की गई ग्राम ज्योति योजना के तहत गांवों में बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करने के साथ ही प्रभावी विद्युत वितरण, ट्रांसफार्मरों, फीडरों एवं उपभोक्ताओं की मानीटरिंग का लक्ष्य था। अक्टूबर 2017 में सौभाग्य योजना के जरिए सुदूर गांवों तक सोलर पैनल पहुंचाकर गरीब परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि विभाग की उपलब्धियां कमतर

रहीं। लेखा परीक्षक ने 16 जिलों के 224 गांवों में 2208 लाभार्थियों पर सर्वेक्षण किया।

रिपोर्ट में साफ किया गया कि योजनाओं के नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन में कमी रही। सौभाग्य योजना में आफ ग्रिड संयोजनों को शामिल करने के आदेश के बावजूद डीपीआर में इस प्रविधान को नहीं रखा गया। परियोजनाओं में 29 से 49 माह तक की देरी की गई। मीटर युक्त उपभोग के आधार पर अग्रिम राजस्व सब्सिडी में असमर्थता के कारण वितरण कंपनियां दो हजार करोड़ रुपये के ऋणों को अनुदान में नहीं बदल सकीं। जीएसटी एवं राज्य करों के त्रुटिपूर्ण दावे किए गए। प्रदेश सरकार से समय पर राज्य करों का दावा न करने की वजह से पश्चिमांचल डिस्काम अपने हिस्से का 4.21 करोड़ रुपये नहीं ले सका। ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरईसी) के ऋण पर 7.19 करोड़

रुपये ब्याज का अधिक भुगतान किया गया। अनावश्यक मर्दों के क्रियान्वयन से खर्च बढ़ा। डीपीआर तैयार करने में लगी फर्मों को 3.33 करोड़ रुपये अधिक भुगतान किया गया। तीन वितरण कंपनियों वाले सात जिलों की रिपोर्ट बताती है कि यहां 72 प्रतिशत कृषि उपभोक्ता अब भी गैर कृषि फीडरों से जुड़े हैं। विद्युत सुरक्षा निरीक्षण शुल्क और जंपरिंग के मद में टर्नकी संविदाकारों (टीकेसीज) को 9.16 करोड़ रुपये अधिक भुगतान किया गया जिसमें से बाद में 5.79 करोड़ रुपये की ही वसूली हो सकी। जांच के दौरान कनेक्शन में दोहरापन पाया गया। इसके लिए 26.65 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान किया गया। जांच के दौरान ज्यादातर लाभार्थियों ने पहले से बिजली आपूर्ति सुधारने की जरूरत बात कही लेकिन कुछ ने वोल्टेज में उतार-चढ़ाव व एलईडी लैंप न मिलने की बात भी कही।

Statement showing Press Clippings regarding coverage of Report of the Comptroller and Auditor General of India on Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana (DDUGJY) and Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana (SAUBHAGYA), Government of Uttar Pradesh, Report No. 7 of the year 2025 (Performance Audit – Commercial) in Newspapers

Date of laying/tabling of Audit Report in the State Legislature: 24.12.2025

Name of the Newspaper	दिनस्तान
Date	25.12.2025
Edition (H/E)	हिंदी
Page No.	13

विद्युत वितरण कंपनियों ने किए अतिरिक्त भुगतान

लखनऊ। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) व प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के प्रबंधन में कई कमियां थीं। भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षा (सीएजी) की रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि सौभाग्य योजना के डीपीआर में आफ-ग्रिड संयोजनों को शामिल नहीं किया गया था। वित्तीय प्रबंधन में कमियों के चलते वितरण कंपनियां दोनों योजनाओं में 2,0026.61 करोड़ रुपये के ऋणों को अनुदान में परिवर्तित नहीं कर पाई थीं।

Statement showing Press Clippings regarding coverage of Report of the Comptroller and Auditor General of India on Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana (DDUGJY) and Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana (SAUBHAGYA), Government of Uttar Pradesh, Report No. 7 of the year 2025 (Performance Audit – Commercial) in Newspapers

Date of laying/tabling of Audit Report in the State Legislature: 24.12.2025.....

Name of the Newspaper	नवभारत टाइम्स
Date	25.12.2025
Edition (H/E)	हिंदी
Page No.	02

मीटर न लगा पाने के कारण बिजली कंपनियों पर बढ़ा 2002.61 करोड़ का कर्ज

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ

प्रदेश के हर परिवार को बिजली कनेक्शन मुहैया करवाने के लिए शुरू की गई सौभाग्य योजना का ठीक से क्रियान्वयन न होने से बिजली कंपनियों का बोझ बढ़ा है। साथ ही योजना के जरिए जिन लक्ष्यों को पाने की कोशिश थी, उसमें भी बिजली कंपनियां नाकाम रही हैं। इसका खुलासा बुधवार को विधानसभा में सौभाग्य योजना और डीडीयूजीजेवाई (दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना) पर पेश की गई सीएजी रिपोर्ट में हुआ है। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक दोनों परियोजनाओं में 29 से 49 महीनों की देरी, एटी ऐंड सी हानियों के लक्ष्य को न पाने और उपभोक्ताओं के घरों में मीटर न लगा पाने के कारण बिजली कंपनियां 2002.61 करोड़ रुपये के ऋण को अनुदान में नहीं बदल पाईं। अब कंपनियों को ये कर्ज चुकाना होगा।

AI Image



CAG
REPORT

● विधानसभा में पेश की गई सीएजी रिपोर्ट

● बिजली कनेक्शनों में दोहराव के चलते हुआ 26.65 करोड़ रुपये का भुगतान

● योजना के खत्म होने पर पूरी रकम नहीं खर्च कर पाई बिजली कंपनियां

रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम ने 66 करोड़ रुपये का अधिक कर्ज लिया, जिसकी वजह से अगस्त, 2021 से जून, 2022 के बीच कंपनी को 3.94 करोड़ रुपये का अधिक ब्याज देना पड़ा। इसके अलावा नियम व शर्तों के

DDUGJY योजना में 96% ही

खर्च (करोड़ रुपये) कर पाई बिजली कंपनियां	स्वीकृत लागत	व्यय
MVVNL	1237.38	1263.01
PUVVNL	1569.07	1505.62
PVVNL	2160.05	2007.11
DVVNL	1979.90	893.02
कुल	6946.40	6668.76

सौभाग्य योजना में आवंटित रकम का सिर्फ 67.44% हुआ खर्च (करोड़ रुपये)

MVVNL	4238.10	2739.35
PUVVNL	4618.41	3382.37
PVVNL	844.94	703.76
DVVNL	2776.34	1589.19
कुल	12477.79	8414.66

घाटे में चल रहे पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को देना पड़ा अधिक ब्याज

उल्लंघन के कारण बिजली कंपनियों को 3.33 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान करना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक ब्याज देरी का सत्यापन न करने के कारण आरईसी लोन पर बिजली कंपनियों को 7.19 करोड़ रुपये अधिक ब्याज का भुगतान करना पड़ा।

डीपीआर तैयार करने वाली कंपनियों को किया गया अधिक भुगतान

रिपोर्ट में पाया गया है कि योजनाओं का डीपीआर तैयार करने वाली एजेंसियों पर भी बिजली कंपनियों ने मेहरबानी दिखाई। मध्यांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम ने योजना का डीपीआर तैयार करने वाली एजेंसियों को 3.33 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान किया।

बिजली कनेक्शनों में दोहराव के चलते हुआ 26.65 करोड़ रुपये का भुगतान

सौभाग्य योजना में ऑडिट के दौरान कई जगहों पर बिजली कनेक्शनों में दोहरापन पाया गया, जिसकी वजह से बिजली कंपनियों को 26.65 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान करना पड़ा। भविष्य में इस तरह के अधिक भुगतान न हो, इसके लिए लेखा परीक्षा ने एजेंसियों के कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए एक सिस्टम बनाने की संस्तुति की है।